

## न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 494/2014

बउनवान

शेकू पुत्र मकसूद जाति—मुसलमान निवासी—ठूसरा  
तहसील—बारां जिला—बारां

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार, बारां



(अपीलांट)

सत्यमेव जयते  
(रेस्पॉडेंट)

Web Copy - Not Official

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी, अभिभाषक

(अपीलांट)

2. परोकार सरकार

(रेस्पॉडेंट)



निर्णय दिनांक— 18.01.2018

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 03.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—ठूसरा, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 388 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 550/-रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली में विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चात्वर्ती अतिक्रमी घोषित करने से पूर्व, पूर्व में प्रार्थी को कब बेदखल किया कोई प्रमाण पत्रावली में मौजूद नहीं है। इसलिये अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व्यवहार प्रक्रिया के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। निर्णय परफोर्मा पर आधारित है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलांट ने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। वर्तमान में उक्त भूमि खाली पड़ी हुई है। तावान राशि जमा करा दी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील प्रोपर

जिला कलक्टर  
बारां (राज०)

नहीं करायी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं दिया है एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। निर्णय परफोर्मा पर है जिसे विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दिया है वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है, भूमि पडत पडी हुई है। उसके विरुद्ध कोई तावान राशि भी बकाया है। अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं करने के लिए वचनबद्ध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

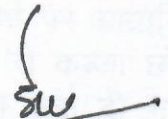
इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 326/11 निर्णय दिनांक 16.03.2011 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर मिसल नम्बर 326/11 निर्णय दिनांक 16.03.2011 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 281/14 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



  
(डॉ०एस.पी.सिंह)  
जिला कलक्टर, बारां  
बारां (राज.)